जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 347 प्रभात कोटा, मंगलवार 30 सितम्बर, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

चीन खुले दिल और मुक्त हाथों से डॉक्टर, इंज़ीनियर व साइंटिस्टों का स्वागत कर रहा है

इससे भारत को दोहरा खतरा है, पहले तो जल्दी ही चीन अमेरिका को पछाड़कर विश्व की नम्बर वन ताकत बन सकता है, दूसरे एशिया के सामरिक संतुलन में चीन अब भारत से बेहिसाब भारी पड़ जायेगा

- इस दौड़ में चीन को दो बातों से मदद मिल रही है, पहली शीर्ष नेतृत्व (राष्ट्रपति शी जिनपिंग) स्वयं आगे बढ़कर स्वागत कर रहे हैं। दूसरी चीन के पास अथाह धन है, इसे फलीभूत करने के लिए। टॉप साइंटिस्ट को लुभाने के लिए चीन 5-5 लाख डॉलर का वार्षिक पैकेज ऑफर कर रहा है।
- चीन के इस प्रयास को सफलता इसलिए भी मिल रही है, क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान (इन्स्टीट्यूट) पहले से ही विद्यमान हैं, इन साइंटिस्टों को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए।
- इसकी तुलना में भारत में कुछ संस्थाएँ हैं और धन भी है, किन्तु विदेश में स्थित इस टेलैंट को लुभाने के लिए संख्या में बहुत कम हैं।
- इस प्रकरण में एक और समस्या है कि इन भारतीय संस्थाओं में पहले से आधिपत्य जमाये लोग नये आने वालों के पैर आसानी से जमने नहीं देना चाहते।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितंबर। डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा एच-1बी वीज़ा के लिए लगाई गई बहुत ऊंची फीस भारत के लिए गंभीर सिरदर्द है। इसका असर केवल भारत के आईटी सेक्टर और अमेरिका को होने वाले सेवा निर्यात पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह भारत के लिए समग्र सुरक्षा परिवेश और रणनीतिक-कूटनीतिक परिदृश्य के लिए भी बड़ी चिंता है।

अन्य बातों के अलावा, अगर चीन अमेरिका से निकल रही बेहतरीन और शीर्ष प्रतिभाओं का अच्छा हिस्सा अपने देश में लाने में कामयाब हो जाता है, तो वह कम समय में अमेरिका पर अपनी तकनीकी रक्षा बढ़त को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल कर पाएगा। यह केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी तात्कालिक चुनौती बन सकती है।

ट्रम्प द्वारा प्रवासी वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों पर की जा रही सख्ती का जिक्र करते हुए सीएनएन ने एक प्रमुख चीनी वैज्ञानिक को उद्धृत किया, जो अब अपने देश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा, चीनी विश्वविद्यालय, एक "कथित" विरोधी से मिले इस अवसर का सक्रिय रूप से लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने लिखी मैलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना

नयी दिल्ली, 29 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि "आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स" इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केवल आत्मकथा नहीं है, यह उनके "मन की बात" है।

प्रधानमंत्री ने मेलोनी की आत्मकथा "आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स" की प्रस्तावना लिखते हुए कहा है, "भारत और इटली

- प्र.मंत्री मोदी ने लिखा, यह इटली की प्र.मंत्री मैलोनी की आत्मकथा मात्र नहीं, बल्कि उनके "मन की बात है।"

संधियों या व्यापार से कहीं ज़्यादा विरासत की रक्षा, समुदाय की मज़बूती और नारीत्व को एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में मानने जैसे साझे मूल्यों से बंधे हैं।" उन्होंने कहा कि दोनों देशों में परंपराओं के प्रति सम्मान और आधुनिकता को अपनाने की एक जैसी भावनाएं मौजूद हैं। मोदी ने इन साझे मूल्यों को अपनी और मेलोनी की व्यक्तिगत मित्रता का आधार बताया है।

उल्लेखनीय है कि इस आत्मकथा की भूमिका में मोदी के अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए

कांग्रेस प्रभारी व महासचिव हरि प्रसाद ने हुड्डा खेमे के पुराने वफादार राव नरेन्द्र सिंह को प्रदेशाध्यक्ष घोषित किया

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। भूपेन्द्र सिंह हूडा हरियाणा में कांग्रेस के निर्विवाद नेता बने हुए हैं, भले ही पार्टी के भीतर उनके विरोधियों ने पिछले विधानसभा चुनाव की हार के लिए उन्हें पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ रखी हो।

- हुड्डा के विरोधी खेमे अब तक यह प्रचार करते रहे हैं कि गत चुनावों में हार का कारण हुड्डा का त्रुटिपूर्ण टिकट वितरण रहा है।
- हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाने के पीछे यह कारण है कि अधिकांश विधायक हुड्डा समर्थक हैं।
- काफी समय से कांग्रेस प्रयास करती रही है कि हरियाणा में दलित नेता हो, पर, वो अब भी यह नहीं कर पाई है।
- बहुत समय से रणदीप सिंह सुरजेवाला पद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु वो हुड्डा खेमे के नहीं हैं, इसलिए उन्हें पद नहीं मिला। एक बार फिर सुरजेवाला, हरियाणा की राजनीति केन्द्रीय स्तर पर करने को मजबूर हैं।

भूपेन्द्र सिंह हूडा को एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता नियुक्त किया गया है, जबकि उनके समर्थक राव नरेन्द्र सिंह को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (पीसीसी) बनाया गया है।

असल में पार्टी की जिम्मेदारी एक बार फिर हूडा को सौंप दी गयी है, क्योंकि हरियाणा में पूरा विधायक दल उन्हीं के साथ खड़ा है।

काफी समय बाद, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी दलित को नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग के नेता चुना है। इसके साथ ही भूपेन्द्र सिंह हूडा राज्य में जाट नेताओं में सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं।

पार्टी संगठन का पुनर्गठन पिछली विधानसभा चुनावों से ही लंबित था और अब आखिरकार एआईसीसी के हरियाणा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद ने सारी अटकलों को खत्म करते हुए, अहम पदों की मंजूरी दे दी है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा में कोई पद पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वे हूडा के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें हरियाणा में कोई जगह नहीं मिल सकी।

सुरजेवाला को हरियाणा से बाहर ही अपनी राजनीति करने पर संतोष करना होगा।

अडानी को प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी, सहारा ग्रुप ने

सहारा समूह का कहना है कि देनदारियां निपटाने व अवमानना कार्यवाही को खत्म करने के लिए संपत्ति बेचने की मंजूरी जरूरी है

- सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
- सहारा समूह ने कहा कि सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24,030 करोड़ रूपए सेबी के रिफंड खाते में जमा करने का आदेश दिया था, इसमें से 1600 करोड़ रूपए जमा कराए जा चुके हैं, बाकी कराने हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितंबर। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ताकि उसे महाराष्ट्र के ऐम्बी वैली और लखनऊ के सहारा शहर सहित, विभिन्न संपत्तियाँ अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मिल सके।

यह याचिका हाल ही में सुनवाई के लिए उल्लेखित की गई थी और संभवतः 14 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है।

वकील गौतम अवस्थी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "सहारा समूह अपनी विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को उस मूल्य और शर्तों पर पूर्ण रूप से बेचने के लिए तैयार है, जैसा कि 6 सितंबर 2025 को हस्ताक्षरित टर्म शीट में उल्लेखित है।"

अंतरिम आवेदन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों और अनुमति प्राप्त करने के बाद, (एसआईसीसीएल) और सहारा समूह ने बड़ी कठिनाई से कुछ चल और अचल संपत्तियों को नकदी में बदला, जिसकी आय सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा की गई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 29 सितम्ब। बीपन नदी के ऊपर 625 मीटर की ऊँचाई पर बना चीनी पुल जो अब दुनिया का सबसे ऊँचा पुल है, बन कर तैयार है, जो घाटी के पार यात्रा के समय को दो घंटे से घटाकर सिर्फ दो मिनट कर देता है।

चीन ने आधिकारिक रूप से

- 625 मीटर ऊंचे पुल से यात्रा का समय 2 घंटे से घट कर 2 मिनट रह गया है।

"हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज" को जनता के लिए खोल दिया है। गुइझोउ प्रांत में स्थित यह अद्भुत वास्तुशिल्प संरचना, 625 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और चीन के सबसे कठिन भू-भागों में कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल देती है।

28 सितंबर को, लाइव ड्रोन फुटेज में देखा गया कि कैसे वाहन इस विशाल पुल को पार कर रहे थे, जिसके नीले सपोर्ट टावर्स नीली सहायक बादलों में आंशिक रूप से छिपे हुए थे।

क्रिकेट मैच के बाद भारत-पाक नेताओं में छिड़ी ज़ुबानी जंग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 29 सितंबर। यह एक दुर्लभ घटना है कि क्रिकेट के खेल के बाद, दो पड़ोसी देशों के राजनीतिक नेताओं के बीच ज़ुबानी जंग छिड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत को 'बैटल सिंदूर' से जोड़ते हुए लिखा कि नतीजा वही रहा, भारत की जीत। इसके बाद, पाकिस्तान के गृहमंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने मोदी की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर युद्ध आपके गर्व का मानदंड था, तो इतिहास हमेशा पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार दर्ज करता है। कोई क्रिकेट मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। खेल में युद्ध को घसीटना सिर्फ हताशा दिखाता है और खेल की मूल भावना का अपमान करता है।

- प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया कप फाइनल में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा और लिखा, "नतीजा वही रहा, भारत की जीत।"
- इस पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने जवाब में लिखा, अगर युद्ध आपके गर्व का मानदंड था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों हुई आपकी अपमानजनक हार को दर्ज करता है।
- सोशल मीडिया भी भारत-पाक क्रिकेट मैच के दौरान दोनों टीमों के व्यवहार पर टीका टिप्पणियों से अटा पड़ा है।

सोशल मीडिया पर भारतीय और पाकिस्तानी टीमों के व्यवहार को लेकर ढेरों टिप्पणियां हो रही हैं। मैदान पर खिलाड़ी हैरिस रऊफ का इशारा, जिससे उसने यह जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के छह विमान मार गिराए थे। इसी प्रकार, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया, जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने, उनके साथ फोटो खिंचवाने और यहां तक कि मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने तक से इनकार कर दिया। नक़वी मेडल और ट्रॉफी लेकर अपने होटल के कमरे में चले गए। कल वह अनोखा क्षण था, जब भारतीय टीम को बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाते देखा गया। सवाल यह उठता है कि अगर रिश्ते इतने कड़वे और तनावपूर्ण हैं, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने का निर्णय किया ही क्यों था? इतिहासकार और खेल लेखक रामचंद्र गुहा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने खेल में राजनीति घुसाकर अपने पद की गरिमा कम कर दी और पाकिस्तानी नेताओं की संस्कृति के स्तर तक उतर गए। गुहा ने कहा कि भारत ने खेलने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि बीसीसीआई वित्तीय लाभ कमाना चाहता था।

गुहा की दलीलें पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। खेल और राजनीति परंपरागत रूप से अलग-अलग क्षेत्र रहे हैं और खेल भावना और आपसी सौहार्द की पवित्रता हमेशा बनाए रखी गई है। कुछ उदाहरणः सन् 1974 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेला था और यहां तक कि रंगभेद के खिलाफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक अधिकृत कश्मीर में न्याय की मांग अब पूर्ण बगावत का रूप ले चुकी है

हज़ारों की संख्या में उत्तेजित जनता सड़कों पर उतर आई है, कर्फ्यू व दबाने की कोशिशों के बावजूद

- सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 29 सितम्बर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर (पीओके) में तूफान उठ रहा है। वर्षों बाद पहली बार, हजारों नाराज़ नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं वो भी कर्फ्यू और दमन को नज़रअंदाज़ करते हुए। अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) द्वारा शुरू की गई न्याय की अपील अब एक पूर्ण जनविद्रोह बन चुकी है - इस्लामाबाद द्वारा दशकों से की गई उपेक्षा और शोषण के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सरकार ने क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है और आधी रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पीओके एक गहरे राजनीतिक संकट के कगार पर खड़ा है।

भारत, जो जम्मू-कश्मीर सहित पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है, के लिए ये विरोध एक रणनीतिक मोड़ है। यह असंतोष पाकिस्तान के उस पुराने दावे को झुठलाता है कि पीओके एक "संतुष्ट" इलाका है, यह आंदोलन इस्लामाबाद के नियंत्रण की आंतरिक कमजोरियों को भी उजागर करता है। नई दिल्ली इसे अपने रूख की पुष्टि के रूप में देखती है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र पर दावा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कि जब उसके खुद के कब्जे वाले इलाके ही असंतोष से उबल रहे हों, तो उसे कश्मीर मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। साथ ही, पीओके में अस्थिरता नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा जोखिम भी बढ़ा सकती है। पाक सरकार की सख्त कार्रवाई शरणार्थी संकट, सीमा पर तनाव या आंतरिक विद्रोह को बाहरी मोर्चे पर मोड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है।

- पाक का यह प्रचार, कि पीओके एक खुशनुमा और संतुष्ट प्रदेश है, अब खोखला साबित हो गया है।
- इस समस्या से पाकिस्तान सरकार पुराने जाने-पहचाने तरीकों से निपटना चाहती है, दमन एवं अर्द्ध सैनिक बलों व सेना के इस्तेमाल से, यहाँ तक कि इंटरनैट व सोशल मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण करके एरिया को अलग-थलग कर आवाज़ों को अपनी मौत मार देना चाहती है।
- यह बगावत सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है, आम जनता सिविल सोसायटी और वकील आदि भी इसका मुखर समर्थन कर रहे हैं। मुज़फ्फराबाद के एक नामी वकील ने कहा है कि आंदोलन मतभेद ज़ाहिर करने का यह प्रजातंत्रीय तरीका है और इसे सुना जाना चाहिए।

इस विद्रोह के केन्द्र में है पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र के लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखना। यह ऐसी भावना है, जो न केवल इस्लामाबाद की आंतरिक स्थिरता पर बल्कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है।

यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब नीलम घाटी सार्वजनिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज़ मीर ने पाक अधिकृत कश्मीर में अनिश्चितकालीन "शटर डाउन और चक्का जाम" हड़ताल की घोषणा की। उनका संदेश स्पष्ट था - वर्षों की उपेक्षा, भ्रष्टाचार और शोषण ने जनता को उबाल पर ला दिया है। मुज़फ्फराबाद से मीरपुर तक, लोग अपने मूलभूत मानव अधिकारों की मांग कर रहे हैं - साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व। जनता का गुस्सा पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर भी है, जिसने कथित रूप से विकास के लिए मिले फंड हड़प लिए और असहमति को दमन के ज़रिए दबा दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)